

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022

प्रलिस के लयि:

मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, भारतमाला परयोजना, त्रपिकषीय समझौता ।

मेन्स के लयि:

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का महत्त्व ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (National Logistics Policy-NLP) 2022 शुरू की है, जिसका उद्देश्य 'अंतिम छोर तक त्वरित वितरण' करना है, साथ ही परिवहन से संबंधित चुनौतियों को समाप्त करना है ।

लॉजिस्टिक्स:

- लॉजिस्टिक्स में संसाधनों, लोगों, कच्चे माल, सूची, उपकरण आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अर्थात् उत्पादन बंदियों से उपभोग, वितरण या अन्य उत्पादन बंदियों तक ले जाने के साथ नियोजन, समन्वय, भंडारण प्रक्रिया शामिल है ।
- लॉजिस्टिक्स शब्द संसाधनों के अधिग्रहण, भंडारण और वितरण को उनके इच्छित स्थान पर न्यंत्रित करने की संपूर्ण प्रक्रिया का वर्णन करता है ।
- इसमें संभावित वितरणों और आपूर्तिकर्तृताओं का पता लगाना तथा ऐसी पार्टियों की व्यवहार्यता एवं पहुँच का मूल्यांकन करना शामिल है ।

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) 2022

परचिय:

- नीति प्रमुख क्षेत्रों जैसे प्रोसेस री-इंजीनियरिंग, डिजिटल इज़ेशन और मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट पर केंद्रित है ।
- यह एक महत्त्वपूर्ण कदम है क्योंकि उच्च लॉजिस्टिक्स लागत अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में घरेलू सामानों की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करती है ।
- एक राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति की आवश्यकता महसूस की गई है क्योंकि भारत में अन्य वकिसति अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में लॉजिस्टिक्स लागत अधिक है ।

लक्ष्य:

- इस नीति की मदद से लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने का प्रयास किया जायेगा । इस नीति का उद्देश्य लागतों में कटौती करना है, जो वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 14-15 प्रतिशत है । जिसमें वर्ष 2030 तक लगभग 8 प्रतिशत तक की कमी लाना है.
 - अमेरिका, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और कुछ यूरोपीय देशों में लॉजिस्टिक्स लागत GDP अनुपात से कम है ।
 - वर्तमान लागत सकल घरेलू उत्पाद का 16% है ।
- दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक्स परफॉर्मंस इंडेक्स (LPI) में शीर्ष 10 में शामिल होना है । उसे दक्षिण कोरिया की विकास गति की बराबरी करनी होगी ।
 - भारत वर्ष 2018 में LPI में 44वें स्थान पर था ।
- कुशल लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करने के लिये डेटा-संचालित नरिणय समर्थन प्रणाली (Decision Support Systems-DSS) बनाना ।
- नीति का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि लॉजिस्टिक मुद्दों को कम-से-कम किया जाए, नरियात कई गुना बढ़े और छोटे उद्योगों एवं उनमें काम करने वाले लोगों को अधिक लाभ मिले ।

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति की विशेषताएँ:

- डिजिटल एकीकरण प्रणाली:** यह नरिबाध और तेज़ी से कार्य की गति को बढ़ाए ताकि लॉजिस्टिक्स सेवाओं को कुशलता के साथ

सुनिश्चित किया जा सके।

- **यूनफाइंड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म:** इसका उद्देश्य सभी लॉजिस्टिक्स और परिवहन क्षेत्र की डिजिटल सेवाओं को एक ही पोर्टल पर लाया जाएगा, जिससे नरिमाताओं एवं नरियातकों को लंबी और बोझिल प्रक्रियाओं जैसी वर्तमान समस्याओं से मुक्ति मिलेगी।
- **लॉजिस्टिक्स सेवाओं में आसानी:** ई-लॉग्स, नया डिजिटल प्लेटफॉर्म, उद्योग को त्वरित समाधान के लिये सरकारी एजेंसियों के साथ परचालन संबंधी मुद्दों को उठाने की अनुमति देगा।
- **व्यापक लॉजिस्टिक्स कार्ययोजना:** व्यापक लॉजिस्टिक्स कार्ययोजना जिसमें **इंटीग्रेटेड डिजिटल लॉजिस्टिक्स सिस्टम**, भौतिक परिसंपत्तियों का मानकीकरण, बेंचमार्क सेवा मानक, मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण, लॉजिस्टिक्स पार्कों का विकास आदि शामिल है।

इस नीतिका महत्त्व क्या है?

- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के शुभारंभ के साथ **पीएम गति शक्ति** को और बढ़ावा एवं पूरकता मिलेगी।
- यह नीति इस क्षेत्र को देश में एक एकीकृत, लागत-कुशल, लचीला तथा सतत **लॉजिस्टिक परतंत्र** बनाने में मदद करेगी क्योंकि यह नियमों को सुव्यवस्थित करने व **आपूर्ति-पक्ष की बाधाओं** को दूर करने के साथ-साथ क्षेत्र के सभी बुनियादों को कवर करती है।
- यह नीति भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार, आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने का एक प्रयास है।

लॉजिस्टिक से संबंधित पहलें:

- [माल का बहुवधि परिवहन अधिनियम, 1993](#)
- [पीएम गति शक्ति योजना](#)
- [मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क](#)
- [लीड्स \(LEADS\) रिपोर्ट](#)
- [डेडविकेटेड फ्रेट कॉरिडोर](#)
- [सागरमाला प्रोजेक्ट्स](#)
- [भारतमाला परियोजना](#)

आगे की राह

- रेल क्षेत्र में कई संरचनात्मक कमियाँ हैं, अगर लॉजिस्टिक लागत को वैश्विक बेंचमार्क पर आधा करना है, तो इन कमियों को तेज़ी से समाप्त करना होगा। एक मालगाड़ी की औसत गति दशकों से 25 कमी प्रति घंटे पर स्थिर रही है- इसे तत्काल दोगुना करके कम-से-कम 50 कमी प्रति घंटे करना होगा।
 - रेलवे को **टाइम-टेबल आधारित माल संचालन** की आवश्यकता है। इसे उच्च-मूल्य के कम लोड वाले व्यवसाय पर न्यंत्रण पाने के लिये **माल दुलाई के स्रोत पर एग्रीगेटर** और गंतव्य पर **डिसिग्रीगेटर** बनना होगा।
- दशकों से देश ने पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी अंतरदेशीय जलमार्ग माल दुलाई की बात की है, लेकिन इस क्षेत्र में कुछ भी प्रगति नहीं हुई है।
 - **चीन के नदी बंदरगाहों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं** जो खासकर पोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जोर देता है।
- रोड लॉजिस्टिक्स पूरी तरह से खंडित क्षेत्र है, जहाँ ट्रक मालिकों के एक बड़े हिससे के पास बहुत छोटा बेड़ा (फ्लीट) है।
 - सरकार द्वारा समर्थित एग्रीगेशन एप्स के साथ छोटे ऑपरेटरों को एक मंच में लाने हेतु सहायक है। साथ ही इस क्षेत्र में बड़ी कंपनियों एवं अभिकर्ताओं को लागत कम करने की ज़रूरत है।
- प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्रों में सुधार के अतिरिक्त **हमें बंदरगाहों का आकार कई गुना और बढ़ाना होगा**, यह अकारण ही नहीं है **कटिनिया के शीर्ष 20 बंदरगाहों में से 10 चीन में हैं**।
- यह **हवाई लॉजिस्टिक्स को नई ऊँचाई पर ले जाने** और उच्च मूल्य एवं खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन में भारी सुधार करने का समय है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. गति-शक्ति योजना के कनेक्टिविटी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सरकार और नजी क्षेत्र के बीच सूक्ष्म समन्वय की आवश्यकता है। विचार-वमिर्श कीजिये। (2022)

स्रोत: पी.आई.बी.

